अंक-4

स्वास्थ्य आपके द्वार...

मासिक न्यूज़लेटर | अप्रैल, 2026

अपर मुख्य सचिव की कलम से...

प्रिय प्रदेशवासियो,

प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस एवं विश्व मलेरिया दिवस के संदर्भ में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, नवाचारों एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को इस अंक के माध्यम से साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 'राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस' (11 अप्रैल) हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोपरांत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में प्रभावी कमी लाने के लिए संचालित नवाचार जैसे - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) और 'सुमन' (SUMAN) पहल मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA), उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की समयबद्ध पहचान, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर देखभाल की सुदृढ़ व्यवस्था, तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। आशा, एएनएम एवं स्वास्थ्य कर्मियों के सक्रिय सहयोग से मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। डिजिटल ट्रैकिंग, मातृ स्वास्थ्य रजिस्ट्रेशन एवं समयबद्ध फॉलो-अप जैसे नवाचारों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित की है। हमारा लक्ष्य Zero Preventable Maternal Deaths (शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु) के लक्ष्य को प्राप्त करना है। विश्व मलेरिया दिवस (25 अप्रैल) के संदर्भ में हमें मच्छर जनित बीमारियों के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करना होगा। यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि विभाग द्वारा संचालित एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम तथा व्यापक जन-जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप हम मलेरिया उन्मूलन की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हैं। दूरदराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में टेस्ट-ट्रीट-ट्रैक (Test-Treat-Track) रणनीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है, जिससे समय पर पहचान, उपचार और निगरानी सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन हेतु बहु आयामी रणनीतियों को सुदृढ़ रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। वेक्टर नियंत्रण गतिविधियाँ-जैसे इनडोर रेसिडुअल स्प्रे (IRS, लार्वा नियंत्रण तथा मच्छरदानियों का वितरण-वृहद स्तर पर संचालित हैं। इसके साथ ही जन-जागरूकता अभियानों, अंतर्विभागीय समन्वय एवं सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से मलेरिया के प्रसार को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

मैं इस अवसर पर विभाग के सभी अधिकारियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करता हूं।

आइए, हम सब मिलकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाने तथा मलेरिया मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सतत प्रयासरत रहें।

अमित कुमार घोष आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
व चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ.प्र.

मिशन निदेशक की कलम से...

प्रिय साथियो,

"स्वास्थ्य आपके द्वार" के इस अंक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस एवं विश्व मलेरिया दिवस जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य विषयों पर प्रदेश में संचालित नवाचारों, उपलब्धियों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम प्रत्येक गर्भवती महिला को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन एवं प्रसवोत्तर सेवाएं सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को और अधिक मजबूत करें। प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिए जाने हेतु जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA), सुमन कार्यक्रम, आपातकालीन प्रसूति सेवाएं हेतु प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफआरयू) का क्रियान्वयन जैसे किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, विशेषज्ञ परामर्श तथा रेफरल सेवाओं की सुदृढ़ व्यवस्था से मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारे 'ई-कवच' पोर्टल और 'मंत्रा' (MaNTrA) ऐप जैसे डिजिटल नवाचारों ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य की निगरानी को एक नई दिशा दी है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रदेश में मलेरिया नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु बहु आयामी रणनीतियों के अंतर्गत व्यापक स्तर पर प्रभावी कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आशा कार्यकत्रियों एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा सामुदायिक जागरूकता, समयबद्ध जांच, त्वरित उपचार तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के माध्यम से मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, डिजिटल सर्विलांस तथा जनसहभागिता आधारित जागरूकता अभियानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली योगदान दिया है।

मुझे विश्वास है कि "स्वास्थ्य आपके द्वार" के इस अंक में संकलित अनुभव, उपलब्धियां एवं नवाचार न केवल विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे, बल्कि जनस्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। आइए, हम सभी मिलकर सुरक्षित मातृत्व एवं मलेरिया मुक्त समाज के निर्माण के लिए अपने प्रयासों को ओर अधिक सुदृढ़ करें तथा स्वस्थ उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें।

डॉ. पिंकी जोवल आई.ए.एस.
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ.प्र.
व सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ.प्र.

मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उत्तर प्रदेश: जमीनी प्रयास, प्रगति और आगे की राह

विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ताकि दुनिया का ध्यान मलेरिया पर केंद्रित रखा जा सके। मलेरिया दुनिया की सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है, फिर भी इसे पूरी तरह से रोका और इसका इलाज किया जा सकता है। विश्व मलेरिया दिवस 2026 के अवसर पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है: "मलेरिया को खत्म करने का संकल्प: अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा।" यह एक ऐसी पुकार है, जो हमें मलेरिया-मुक्त भविष्य के लिए प्रेरित करती है।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध भौगोलिक परिदृश्य वाले राज्य में मलेरिया नियंत्रण एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया रही है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। यह प्रगति स्वास्थ्य विभाग, फील्ड कार्यकर्ताओं और समुदाय की साझेदारी का परिणाम है।

मलेरिया एक वेक्टर जनित संक्रामक रोग है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग मुख्यतः उन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, जहां जलभराव, स्वच्छता की कमी और पर्यावरणीय परिस्थितियां मच्छरों के प्रजनन के अनुकूल होती हैं। समय पर पहचान और उपचार न मिलने पर यह गंभीर रूप ले सकता है, किंतु उचित जांच और समयबद्ध उपचार से इसे पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मलेरिया नियंत्रण का मूल आधार है-समय पर पहचान, सटीक जांच और पूर्ण उपचार।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 के बाद मलेरिया की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2019 में जहां मलेरिया के 92,000 से अधिक मामले सामने आए थे, वहीं वर्ष 2024 और 2025 तक यह संख्या घटकर लगभग 13,477-14,590 के बीच रह गई है। यह गिरावट केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, बल्कि सुदृढ़ निगरानी प्रणाली, बेहतर डायग्नोस्टिक सुविधाओं और लगातार किए जा रहे वेक्टर नियंत्रण प्रयासों की सफलता को दर्शाती है। साथ ही, पी. फाल्सीपेरम (Plasmodium falciparum) के मामलों का अनुपात भी कम रहा है, जो प्रभावी केस मैनेजमेंट, समय पर पहचान और उचित उपचार का संकेत देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि न केवल मामलों की संख्या कम हुई है, बल्कि रोग की गंभीरता को भी नियंत्रित किया जा सका है।

निगरानी तंत्र में सुधार को वार्षिक रक्त परीक्षण दर (Annual Blood Examination Rate - ABER) में वृद्धि से भी समझा जा सकता है। वर्ष 2019 में जहां ABER 2.51% था, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 7.8% तक पहुंच गया है, जो 7% के राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है। इसके साथ ही, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट (TPR) लगातार 0.25% से नीचे बना हुआ है, जो अत्यंत संवेदनशील और प्रभावी निगरानी का संकेत है। इसका अर्थ है कि अधिक संख्या में लोगों की जांच हो रही है और संक्रमण की पहचान प्रारंभिक स्तर पर ही की जा रही है।

राज्य में मलेरिया नियंत्रण के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत समन्वित रणनीति लागू की जा रही है। "राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य 2030" को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023-27 (NSP 2023-27) एक स्पष्ट दिशा प्रदान करती है।

इस रणनीति का **पहला प्रमुख आधार** है-मलेरिया निगरानी को मुख्य हस्तक्षेप के रूप में स्थापित करना। NSP 2023–27 के अंतर्गत निगरानी को एक case-based, real-time system के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें प्रत्येक मामले की पहचान, उसके स्रोत का पता लगाना और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है। "1-3-7" समयसीमा के तहत एक दिन के भीतर केस की सूचना, तीन दिन के भीतर जांच और सात दिन के भीतर फोकस क्षेत्र में आवश्यक नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं। सक्रिय एवं प्रतिक्रियात्मक केस खोज तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से पूर्ण रिपोर्टिंग इस प्रणाली को और सुदृढ़ बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश में मलेरिया नियंत्रण हेतु सुदृढ़ निगरानी, त्वरित जांच, समयबद्ध उपचार और सामुदायिक सहभागिता से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। "टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक" रणनीति के माध्यम से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए मलेरिया-मुक्त लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।

दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है-"Test, Treat and Track" अर्थात प्रत्येक संदिग्ध मरीज की जांच, पुष्ट मामलों का उपचार और उनकी निगरानी। आशा, एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) अब RDTs का उपयोग करके दूरदराज के क्षेत्रों में भी त्वरित जांच सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे निदान में देरी नहीं होती। सभी पुष्ट मामलों को राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार उपचार दिया जाता है और दवा का पूरा कोर्स सुनिश्चित किया जाता है। उपचार के बाद फॉलो-अप और केस ट्रैकिंग भी इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

तीसरा स्तंभ मलेरिया की रोकथाम को सुदृढ़ करना है, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट अपनाया जा रहा है। इसमें मच्छरों की प्रजातियों, उनके प्रजनन स्थलों और कीटनाशक प्रतिरोध की निगरानी की जाती है तथा IRS और लार्वा नियंत्रण जैसे उपायों को क्षेत्र विशेष के अनुसार लागू किया जाता है। इससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सहायता मिलती है।

चौथा स्तंभ मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्रयासों को गति देना है। "शून्य स्वदेशी मलेरिया" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर माइक्रो-प्लानिंग, रियल-टाइम डेटा-आधारित निर्णय और नियमित समीक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और बहुक्षेत्रीय समन्वय भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पांचवां स्तंभ अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित निर्णय को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत UDSP पोर्टल पर रियल-टाइम सूचना प्राप्त होती है और 24 से 48 घंटे के अंतर्गत उसका इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे कार्यक्रम को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाया जा रहा है।

इन सभी रणनीतियों का प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर, बरेली जनपद के एक गांव में बुखार से पीड़ित आदित्य की समय (17 अप्रैल) पर पहचान की गई। आशा कार्यकर्ता द्वारा तत्काल RDT जांच कराई गई, जिसमें मलेरिया की पुष्टि हुई। मरीज को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र तक रेफर किया गया, उसका मलेरिया कार्ड बनाया गया और दवा का पूरा कोर्स आशा के सुपरविजन में चल रहा है। आशा द्वारा दो बार फॉलो-अप भ्रमण किया जा चुका है। परिवार को मच्छरजनित रोगों से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। परिणामस्वरूप, मरीज शीघ्र स्वस्थ हुआ और संक्रमण के आगे फैलाव को रोका जा सका। यह उदाहरण दर्शाता है कि सुदृढ़ निगरानी, त्वरित जांच और फॉलो-अप रणनीति कितनी प्रभावी है। मलेरिया नियंत्रण में सामुदायिक सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जलभराव को रोकना, कूलर और अन्य जल स्रोतों की नियमित सफाई, मच्छरदानी का उपयोग और व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय अपनाना संक्रमण के जोखिम को कम करने में सहायक हैं। विभाग द्वारा फॉगिंग, एंटी-लार्वा गतिविधियां और स्वच्छता अभियान निरंतर संचालित किए जा रहे हैं, जो इन प्रयासों को और सुदृढ़ करते हैं।

अंततः, मलेरिया के विरुद्ध यह लड़ाई बहु-आयामी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, जमीनी कार्यकर्ता, साझेदार संस्थाएं और समुदाय-सभी की समान भूमिका है। सुदृढ़ निगरानी, प्रभावी उपचार और सतत रोकथाम उपायों के माध्यम से "मलेरिया मुक्त उत्तर प्रदेश" का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

डॉ. वी. के. सिंघल
संयुक्त निदेशक, मलेरिया
उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026: समानता, सम्मान और सुरक्षित मातृत्व का संकल्प

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है, इस वर्ष 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की थीम: "Equity in Maternal Healthcare: Leaving No Mother Behind" (मातृ स्वास्थ्य देखभाल में समानता: कोई भी गर्भवती माता पीछे न छूटे) है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान एवं प्रसवोपरांत समस्त चिकित्सीय सेवाएं निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण मिलें, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय की हो, भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां बाधा न बनें। समानता के नज़रिये से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस (National Safe Motherhood Day) सिर्फ एक दिवस नहीं बल्कि महिलाओं के Human Rights & Gender Justice का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम समानता की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि हर महिला को, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसे सम्मानजनक, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित मातृत्व लाभ मिलनी ही चाहिए।

प्रदेश में सम्मानजनक मातृत्व देखभाल (Respectful Maternity Care - RMC)

- प्रत्येक महिला को समुचित उपचार प्राप्त करने तथा गलत और जोखिमयुक्त उपचार से मुक्त रहने का अधिकार है। कोई भी आपको शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है।
- प्रत्येक महिला को प्रसव तथा शिशु जन्म के समय तीमारदार के चयन और प्राथमिकताओं के प्रति सम्मान, सूचना, सहमति और इनकार का अधिकार है, "आपकी जानकारी एवं सहमति उपरांत ही आपका उपचार किया जाता है।"
- प्रत्येक महिला को गोपनीयता एवं निजता का पूर्ण अधिकार है। "कोई भी आप की निजी जानकारियों को किसी के समक्ष प्रकट नहीं कर सकता है।"

- प्रत्येक महिला गरिमा एवं सम्मान के साथ उपचार प्राप्त करने का अधिकार रखती है। "आपको कोई अपमानित नहीं कर सकता, मौखिक रूप से कोई अभद्रता भी नहीं कर सकता है।"
- प्रत्येक महिला को समानता, भेदभाव से मुक्त और न्यायसंगत देखभाल का अधिकार है। "कोई आपसे इसलिए भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि उसे आपसे सम्बंधित कोई तथ्य पसंद नहीं है।"
- प्रत्येक महिला को स्वतंत्रता, स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता और नियंत्रण या दबाव से आज़ादी का अधिकार है।

Reproductive Rights, Equality & Decision Making

- समानता का पहला कदम महिलाओं का अपने शरीर एवं स्वास्थ्य पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए।
- महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने स्वास्थ्य से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके।
- सुरक्षित मातृत्व की जिम्मेदारी सिर्फ महिला की ही नहीं, पुरुषों एवं परिवार की भी बराबर होनी चाहिए।
- गर्भावस्था के दौरान पति का सहयोग एवं जानकारी होना Gender Equality की तरफ एक बड़ा कदम है।
- सामान्यतः पाया गया है कि गर्भावस्था से संबंधित फैसले (अस्पताल कब जाना है, क्या खाना है इत्यादि) परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, जिस पर गर्भवती महिला का समान अधिकार होना चाहिए।

आर्थिक समानता (Economic Equality)

- जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वह पोषण पर ध्यान दे सके, इसकी संपूर्ण जानकारी उन्हें होनी चाहिए।

रायबरेली जनपद में Ferric Carboxymaltose (FCM) इंजेक्शन से एनीमिया प्रबंधन

जनपद रायबरेली में Ferric Carboxy Maltose (FCM) इंजेक्शन के संबंध में पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया, जिसमें जनपद रायबरेली के समस्त FRU एवं जिला महिला चिकित्सालय के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं स्टाफ नर्सों का Ferric Carboxy Maltose (FCM) एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रशिक्षण किया गया।

सफलता की कहानी - सीवियर एनीमिक गर्भवती महिला का सफल प्रबंधन (FCM थेरेपी के माध्यम से)

जनपद रायबरेली में सीवियर एनीमिया के प्रभावी प्रबंधन हेतु किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. नवीन चंद्रा के निर्देशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ऊंचाहार पर Ferric Carboxy Maltose (FCM) इंजेक्शन के माध्यम से एक गर्भवती महिला का सफल उपचार किया गया।

इस पहल के सफल क्रियान्वयन में नोडल अधिकारी RCH- डॉ. शरद कुशवाहा, FRUCHC ऊंचाहार चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज शुक्ला, UP-TSU की डॉ. शिवांगी शुक्ला (सीनियर डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट - मातृ एनीमिया) एवं मैटरनल हेल्थ कंसल्टेंट रायबरेली यासीन अहमद द्वारा किए गए निरंतर प्रयास (continuous efforts) एवं सुदृढ़ फॉलो-अप (rigorous follow-up) का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके प्रयासों से जनपद के सभी FRU पर कार्यरत स्टाफ नर्स एवं चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कराया गया तथा FCM सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 21 मार्च 2026 को "वर्ल्ड एनीमिया डे" के अंतर्गत FRU ऊंचाहार में गंभीर एनीमिक महिला को FCM इंजेक्शन प्रदान किया गया।

लाभार्थी का विवरण- नाम - संजना पता - कलरगंज, बछरावां, रायबरेली (ऊंचाहार)

उक्त गर्भवती महिला गंभीर एनीमिया से ग्रसित थी, जिनका प्रारंभिक हीमोग्लोबिन (Hb) स्तर 6.8 g/dl था। प्रशिक्षित महिला चिकित्सक डॉ. वान्या मिश्रा की देखरेख में स्टाफ नर्स काजल के माध्यम से उक्त महिला को FCM इंजेक्शन प्रदान किया गया।

उपचार के उपरांत किए गए पोस्ट-टेस्ट में महिला का हीमोग्लोबिन स्तर बढ़कर 8.9 g/dl हो गया, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है। यह FCM थेरेपी की प्रभावशीलता का प्रमाण है।

इस प्रक्रिया में ANM किरण मिश्रा एवं ASHA संगम देवी द्वारा लाभार्थी की पहचान एवं फॉलो-अप में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। साथ ही, फील्ड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग, सपोर्टिव सुपरविजन, डेटा संकलन एवं समुचित डॉक्यूमेंटेशन भी सुनिश्चित किया गया।

यह सफलता की कहानी दर्शाती है कि प्रभावी नेतृत्व के साथ-साथ निरंतर प्रयास एवं सुदृढ़ निगरानी के माध्यम से FCM थेरेपी गंभीर एनीमिया के प्रबंधन में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राधिका मणि (CHO, सदर ब्लॉक, नटवा), जनपद महाराजगंज

सुश्री राधिका मणि, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO), पिछले 3 वर्षों से सदर ब्लॉक, नटवा में कार्यरत हैं। इस दौरान इन्होंने विशेष रूप से NCD (Non-Communicable Disease) जैसे उच्च रक्तचाप (BP) और मधुमेह (Diabetes) की रोकथाम, जांच और प्रबंधन पर निरंतर कार्य किया है।

एक प्रेरणादायक उदाहरण:

मेरे क्षेत्र की एक गर्भवती महिला जांच के लिए आईं, जिनका BP और शुगर-दोनों बढ़ा हुआ पाया गया। शुरुआत में वह अपनी स्थिति को लेकर गंभीर नहीं थीं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया और नियमित जांच व दवा लेने के लिए प्रेरित किया। लगातार फॉलो-अप और सही देखभाल के कारण उनका BP और शुगर नियंत्रण में आ गया और अंततः उन्होंने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत संतोषजनक और प्रेरणादायक रहा। मैं मरीजों को न केवल दवा उपलब्ध कराती हूं, बल्कि उन्हें सही खान-पान (Diet) और जीवनशैली में सुधार के लिए भी प्रेरित करती हूं। नियमित फॉलो-अप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज समय पर दवा लें और अपनी सेहत

का ध्यान रखें।

मेरा उद्देश्य आगे भी इसी प्रकार कार्य करते हुए अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना है। मैं सभी से अपील करती हूं कि नियमित जांच कराएं, संतुलित आहार लें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।

जालौन जनपद में CHC पर MAMC बनने से गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से राहत

जालौन जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर MAMC (Maternal Anemia Management Centre) की स्थापना के बाद गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के उपचार में उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में विकास खंड माधौगढ़ के ग्राम पंचायत चाकी की निवासी 23 वर्षीय श्रीमती हेमलता देवी (पति-मनीष) का मामला एक सफल उदाहरण के रूप में सामने आया है।

हेमलता देवी ने अपनी गर्भावस्था की जानकारी अपनी आशा बहन श्रीमती रमा देवी को दी। आशा द्वारा समय पर पंजीकरण सुनिश्चित किया गया तथा उन्हें VHSND सत्र में प्रथम प्रसव पूर्व जांच (ANC) हेतु बुलाया गया। जांच के दौरान एएनएम द्वारा किए गए परीक्षण में उनका हीमोग्लोबिन स्तर 7.6 ग्राम/डीएल पाया गया, जो मध्यम एनीमिया की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात उन्हें आयरन फोलिक एसिड (IFA) एवं कैल्शियम की गोलियां प्रदान की गईं। उनका अंतिम मासिक धर्म (LMP) 25 फरवरी 2025 था, जिसके आधार पर अनुमानित प्रसव तिथि (EDD) 4 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई।

आशा एवं आशा संगिनी द्वारा नियमित गृह भ्रमण एवं फॉलो-अप के दौरान द्वितीय ANC जांच कराई गई, जिसमें हीमोग्लोबिन स्तर 7.5 ग्राम/डीएल पाया गया। स्थिति में अपेक्षित सुधार न होने पर एएनएम द्वारा उन्हें आयरन सुक्रोज थेरेपी हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधौगढ़ (MAMC) के लिए रेफर किया गया।

प्रारंभ में परिवार द्वारा अस्पताल जाकर इंजेक्शन उपचार कराने में अनिच्छा व्यक्त की गई, परंतु आशा एवं आशा संगिनी द्वारा निरंतर परामर्श एवं समझाइश के माध्यम से उन्हें एनीमिया के संभावित जोखिमों से अवगत कराया गया। अंततः परिवार सहमत हुआ और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के अंतर्गत हेमलता को CHC माधौगढ़ लाया गया।

CHC पर पुनः जांच में हीमोग्लोबिन स्तर 7.5 ग्राम /डीएल पाया गया। चिकित्सक द्वारा स्थिति का मूल्यांकन कर यह निर्णय लिया गया कि केवल IFA टैबलेट्स से सुधार संभव नहीं है, अतः आयरन सुक्रोज इंजेक्शन थेरेपी प्रारंभ की गई। निर्धारित अंतराल पर हेमलता को कुल 5 डोज (200 mg/10 ml प्रति डोज) आयरन सुक्रोज प्रदान किया गया। पहली डोज 18-10-2025 को तथा अंतिम डोज 03-11-2025 को दी गई। प्रत्येक डोज सुनिश्चित कराने में आशा कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उपचार के साथ-साथ आहार परामर्श भी दिया गया, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, गुड़, चुकंदर एवं अनार जैसे पोषक तत्वों को भोजन में शामिल करने की सलाह दी गई तथा नियमित IFA सेवन हेतु प्रेरित किया गया। उपचार के पश्चात हेमलता की स्थिति में निरंतर सुधार देखा गया। पूर्व में अत्यधिक कमजोरी एवं थकान की शिकायत रहने के

स्थान पर अब वह अधिक सक्रिय एवं ऊर्जावान महसूस करने लगीं। लगभग डेढ़ माह पश्चात पुनः हीमोग्लोबिन जांच में स्तर 8.9 ग्राम/डीएल पाया गया। इस सुधार के परिणामस्वरूप 11 दिसंबर 2025 को उनका सुरक्षित एवं सफल प्रसव संभव हो सका।

हेमलता एवं उनके परिवार द्वारा इस उपचार एवं मार्गदर्शन के प्रति संतोष व्यक्त किया गया। यह प्रकरण दर्शाता है कि समय पर पहचान, उचित रेफरल, MAMC पर उपलब्ध सेवाएं तथा आशा कार्यकर्ताओं के सतत प्रयासों से मध्यम एवं गंभीर एनीमिया जैसी जटिल स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।